All Inclusive IAS - Prelims 2024

← English video | Economy Class-02 | हिंदी वीडियो →

Poverty in India

NEWS

Global Hunger Index: India's rank 111/125 Link
Govt extended free food for 80 crore people Link
NITI Aayog's report on Multidimensional poverty Link

ग्लोबल हंगर इंडेक्स: भारत की रैंक 111/125 Link
सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देगी Link
बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट Link

Headcount ratio : percentage of people living in poverty

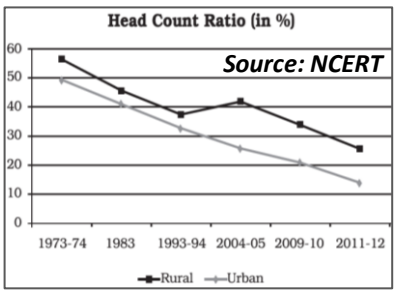

हेड काउंट रेशियो : कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में रह रही है

What causes poverty?
- ✓ social, economic, political inequality
- ✓ social exclusion
- ✓ unemployment
- ✓ indebtedness
- ✓ unequal distribution of wealth

गरीबी का कारण क्या है?
- ✓ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता
- ✓ सामाजिक बहिष्कार
- ✓ बेरोजगारी
- ✓ ऋणग्रस्तता
- ✓ धन का असमान वितरण

Poverty is also caused by economy-wide problems:
- ✓ low capital formation
- ✓ lack of infrastructure
- ✓ lack of demand
- ✓ pressure of population
- ✓ lack of social/welfare nets

गरीबी अर्थव्यवस्था-व्यापी समस्याओं के कारण भी होती है:
- ✓ कम पूंजी निर्माण
- ✓ बुनियादी ढांचे की कमी
- ✓ मांग की कमी
- ✓ जनसंख्या का दबाव
- ✓ सामाजिक/कल्याणकारी तंत्रों की कमी

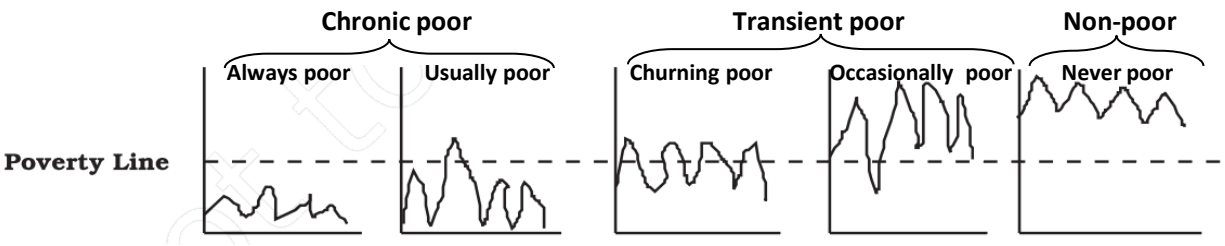

Consumption (not income) is a better measure of poverty.
Reason: income is seasonal, fluctuates, not reported honestly.
Think: a businessman earned 50 lakh/year for 5 years. In 6th year, he incurred loss of Rs 2 lakh. Does this mean he is poor?

उपभोग (आय नहीं) गरीबी का बेहतर माप है।
कारण: आय मौसमी है, उतार-चढ़ाव होता है, लोग सच नहीं बताते हैं।
सोचो: एक व्यापारी ने 5 साल 50 लाख/वर्ष कमाए। छठे वर्ष में, उसे 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ। तो क्या वह गरीब है?

Attempts to define Poverty
- ❑ Planning Comm Working Group 1962
- ❑ Dandekar and Rath in 1971
- ❑ Alagh Committee in 1979
- ❑ Lakdawala Committee in 1993
- ❑ Tendulkar Committee in 2009
- ❑ Rangarajan Committee in 2014

1962 में योजना आयोग का कार्य समूह
1971 में दांडेकर और रथ
1979 में अलघ समिति
1993 में लकड़ावाला समिति
2009 में तेंदुलकर समिति
2014 में रंगराजन समिति।

"Poverty Problem in India" book by Prithwis Chandra Ray in 1895
"Poverty and Un-British Rule in India" book by Dadabhai Naoroji in 1901

"भारत में गरीबी की समस्या" 1895 में प्रकाशित, पृथ्वी चंद्र रे की पुस्तक
"पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया" 1901 में प्रकाशित, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDG 1 : No poverty
SDG 1.1 : Eradicate extreme poverty
SDG 1.2 : Reduce poverty by at least 50%

SDG 1 : कोई गरीबी नहीं
SDG 1.1 : अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन
SDG 1.2 : गरीबी को कम से कम 50% तक कम करें

Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)
It is an arm of IMF which lends to world's poorest countries.
It started in 1999 by replacing Enhanced Structural Adjustment Facility.

यह IMF की एक शाखा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों को उधार देती है। इसकी शुरुआत 1999 में एन्हांस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी को रिप्लेस करके हुई थी

Human Poverty Index
- It was introduced in Human Development Report in 1997.
- In 2010, it was replaced by MPI.

मानव गरीबी सूचकांक
- इसे 1997 में HDR में पेश किया गया था
- 2010 में, इसे MPI द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

Separate explanation videos are available in English & Hindi | अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

Multidimensional Poverty Index

Three dimensions	Global MPI 10 indicators	National MPI 12 indicators
(1/3) Health	Nutrition	-
	Child mortality	-
		Maternal health
(1/3) Education	Years of schooling	-
	School attendance	-
(1/3) Living standard	Cooking fuel	-
	Sanitation	-
	Drinking water	-
	Electricity	-
	Housing	-
	Assets	-
		Bank account

Note: Per capita income, Literacy rate, and Life expectancy are not indicators

बहुआयामी गरीबी सूचकांक

तीन आयाम	ग्लोबल MPI 10 संकेतक	राष्ट्रीय MPI 12 संकेतक
(1/3) स्वास्थ्य	पोषण	-
	बाल मृत्यु दर	-
		मातृ स्वास्थ्य
(1/3) शिक्षा	स्कूली शिक्षा के वर्ष	-
	स्कूल अटेंडेंस	-
(1/3) जीवन स्तर	खाना पकाने का ईंधन	-
	स्वच्छता	-
	पेयजल	-
	विद्युत	-
	आवास	-
	परिसंपत्ति	-
		बैंक खाता

नोट: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा संकेतक नहीं हैं

Global Multidimensional Poverty Index

- → It is based on Alkire & Foster (AF) methodology.
- → It uses dual-cutoff counting method.
- → It assesses poverty at individual level.
- → If a person is deprived in a third or more of ten (weighted) indicators, it identifies them as poor.

- → यह Alkire & Foster (AF) पद्धति पर आधारित है
- → यह दोहरी कटऑफ गिनती पद्धति का उपयोग करता है
- → यह व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी का आकलन करता है
- → यदि कोई व्यक्ति दस (भारित) संकेतकों में से एक तिहाई या अधिक में वंचित है, तो यह उन्हें गरीब के रूप में पहचानता है

2023 report: 110 crore people in 110 countries live in acute multidimensional poverty

2023 report: 110 देशों में 110 करोड़ लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं

India: (pre-covid data)
- During 2005-15, 27 crore people came out of poverty
- During 2005-20, 41 crore people came out of poverty

भारत: (प्री-कोविड डेटा)
- 2005-15 के दौरान 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए
- 2005-20 के दौरान 41 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए

It considers both incidence and intensity of poverty, hence it is known as adjusted headcount ratio.

MPI = H x A

H = incidence of poverty (Headcount ratio)

A = intensity of poverty (How poor are the poor)

यह गरीबों की संख्या और गरीबी की तीव्रता, दोनों को मानती है, इसलिए इसे समायोजित हेडकाउंट अनुपात के रूप में जाना जाता है

MPI = H x A

H = हेड काउंट रेशियो (कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं)

A = गरीबी की तीव्रता (गरीब , कितना गरीब है)

- ❑ MPI was developed in 2010 by UNDP and OPHI (Oxford Poverty & Human Development Initiative)
- ❑ It is published along with Human Development Index (HDI) in Human Development Report (HDR).

- ❑ MPI को 2010 में UNDP और OPHI द्वारा विकसित किया गया था
- ❑ इसे मानव विकास रिपोर्ट (HDR) में मानव विकास सूचकांक (HDI) के साथ प्रकाशित किया जाता है।

National Multidimensional Poverty Index

Link NITI Aayog has published the report "Multidimensional Poverty in India since 2005-06"

NITI Aayog's National MPI *(first released in 2021)*
- → It uses Global MPI, but includes two more indicators - Maternal Health and Bank Accounts.
- → It used NFHS data for some years, and estimated the numbers for other years.

Link नीति आयोग ने रिपोर्ट प्रकाशित की है "2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी"

NITI आयोग का राष्ट्रीय MPI *(पहली बार 2021 में रिलीज़)*
- → यह ग्लोबल MPI का उपयोग करता है, लेकिन इसमें दो और संकेतक शामिल हैं - मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते
- → इसने कुछ वर्षों के लिए NFHS डेटा का उपयोग किया, और अन्य वर्षों के लिए संख्याओं का अनुमान लगाया है

- → Poverty declined more in Rural, than Urban areas.
- → Improvement was seen in all 12 indicators.
- → Both incidence and intensity declined.
- → Fastest decline in number of poor: UP
- → Fastest decline in headcount ratio: Bihar
- → India will achieve SDG 1.2 much before 2030.

- → शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक घटी है
- → सभी 12 संकेतकों में सुधार देखा गया है
- → संख्या और तीव्रता दोनों में गिरावट आई है
- → गरीबों की संख्या में सबसे तेज गिरावट: उत्तर प्रदेश
- → हेड काउंट रेशियो में सबसे तेज गिरावट: बिहार
- → भारत 2030 से बहुत पहले SDG 1.2 हासिल कर लेगा

Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

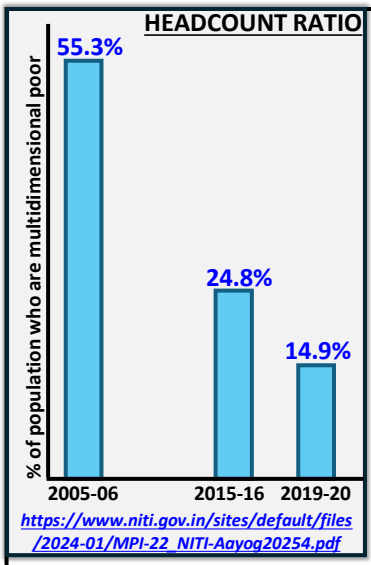

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-01/MPI-22_NITI-Aayog20254.pdf

***Criticism of the report** रिपोर्ट की आलोचना* Link Link

It ignores Covid's impact on poverty

- It assumes that during 2020-2023, poverty declined at same rate as 2015-2020.
- Hence it concludes that in 2023, only 11% people (15 crore) in India are poor.

It uses bank account, and not money in bank account, as indicator

- 4.30 crore Jan Dhan accounts have zero rupee (Nov 2023, PIB)
- Many Jan Dhan accounts have only 1 rupee (September 2016, IE)

Is the person with empty bank account not poor?

यह रिपोर्ट गरीबी पर कोविड के प्रभाव को नजरअंदाज करती है

- रिपोर्ट कहती है कि 2020-2023 के दौरान, गरीबी 2015-2020 के समान दर से घटी है।
- इस धारणा के आधार पर, रिपोर्ट कहती है कि 2023 में भारत में केवल 11% लोग (15 करोड़) गरीब हैं।

यह संकेतक के रूप में बैंक खाते को देखती है, न कि बैंक खाते में मौजूद पैसे को

- 4.30 करोड़ खातों में 0 रुपया है। (नवंबर 2023, PIB)
- कई खातों में केवल 1 रुपया है। (सितंबर 2016, IE)

क्या खाली बैंक खाते वाला व्यक्ति गरीब नहीं होता है?

Global Indices for Reforms and Growth (GIRG) Link

→ Govt tracks India's rank in selected Global Indices (presently 30)
→ Each State/UTs is also given a rank based on its performance
→ Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO) under NITI Aayog is the knowledge partner.

→ कुछ वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंक (वर्तमान में 30) को भारत सरकार ट्रैक करती है
→ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उसके प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी जाती है
→ नीति आयोग का DMEO इसमे ज्ञान भागीदार है

Prelims 2019

In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in other because

(a) Poverty rates vary from state to state
(b) Price levels vary from state to state
(c) Gross state product varies from state to state
(d) Quality of public distribution varies from state to state

किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि

a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है
b) कीमत स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है
c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है
d) सार्वजनिक वितरण की गुणता एक राज्य अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है

Prelims 1994 To know whether the rich are getting richer and the poor getting poorer, it is necessary to compare

(a) wholesale price index over different periods of time for different regions
(b) distribution of income of an identical set of income recipients in different periods of time
(c) distribution of income of different sets of income recipients at a point of time
(d) availability of foodgrains among two sets of people, one rich and other poor, over different periods of time

यह जानने के लिए कि क्या अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहे हैं, तुलना करना आवश्यक है

a) विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समय में थोक मूल्य सूचकांक
b) समय की विभिन्न अवधियों में आय प्राप्तकर्ताओं के एक समान समूह की आय का वितरण
c) एक समय पर आय प्राप्तकर्ताओं के विभिन्न समूहों की आय का वितरण
d) लोगों के दो समूहों, एक अमीर और दूसरा गरीब, के बीच अलग-अलग समय में खाद्यान्न की उपलब्धता

Practice Question Which of the following govt initiatives have helped in reducing poverty in India?

1. RTI Act 2005 Link ✓
2. MNREGA Act 2005 Link ✓
3. Rashtriya Swasthya Bima Yojana 2008 Link ✓
4. National Food Security Act 2013 Link ✓
5. Direct Benefit Transfer 2013 Link ✓

निम्नलिखित में से किस सरकारी पहल ने भारत में गरीबी को कम करने में मदद की है?

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 Link
2. मनरेगा अधिनियम 2005 Link
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 Link
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 Link
5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 2013 Link

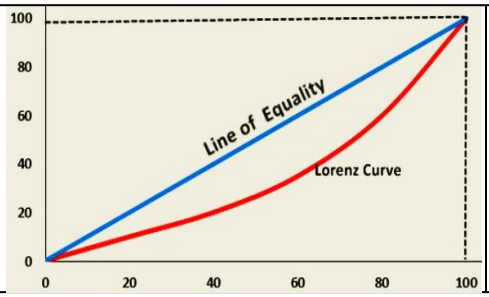

Lorenz curve shows distribution of income or wealth

Gini index shows inequality
Zero means zero inequality
One means full inequality

Poverty gap
(poverty line) - (average income of poor)

लोरेन्ज वक्र आय या धन का वितरण दर्शाता है।

गिनी सूचकांक असमानता को दर्शाता है।
शून्य मतलब शून्य असमानता।
एक मतलब पूर्ण असमानता।

गरीबी अंतर = (गरीबी रेखा) - (गरीबों की औसत आय)

Direct Benefit Transfer

Identify the Problem → **Implement the Solution** → **Enjoy the result**

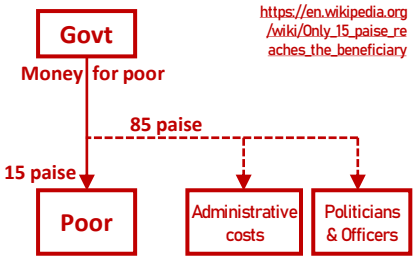

https://en.wikipedia.org/wiki/Only_15_paise_reaches_the_beneficiary

2005 RTI: to bring transparency in system Link

2008 NPCI: to create infra for a modern payment system Link

2009 PFMS: to track govt funds Link

2009 Aadhaar: to end fake beneficiaries Link

2013 DBT: to transfer benefits directly into bank account of beneficiary Link

2015: Guinness certificate of LPG subsidy transfer handed over to Modi *News*

2020: Massive achievement of Modi govt! Over ₹ 1 lakh crore saved because of DBT: FM *News*

2024: DBTs totaling ₹ 34 lakh crore resulted in savings of ₹ 2.7 lakh crore to govt: FM *News*

https://dbtbharat.gov.in/static-page-content/spagecont?id=1

- DBT was started on 1st January 2013
- It was launched under Planning Commission
- It now comes under Cabinet Secretariat
- JAM i.e. Jan Dhan*, Aadhaar and Mobile are DBT enablers

* 2005: No frills account, 2012: BSBDA, 2014: Jan Dhan

- DBT 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था
- इसे योजना आयोग के अंतर्गत शुरू किया गया था
- यह अब कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आता है
- JAM (जन धन*, आधार मोबाइल) से DBT संभव है

* 2005: No frills account, 2012: BSBDA, 2014: Jan Dhan

https://pfms.nic.in/SitePages/doc/PFMS_DBT_FAQ.pdf

What is Direct Benefit Transfer? It an initiative to transfer benefits directly into the bank account of the beneficiary.

Is Aadhaar mandatory for DBT? No. But it is desirable to achieve DBT objectives in its true sense.

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है? यह लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे लाभ हस्तांतरित करने की एक पहल है

क्या DBT के लिए आधार अनिवार्य है? नहीं, लेकिन सही अर्थों में DBT उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आधार वांछनीय है

https://pfms.nic.in/SitePages/aboutus.aspx

- PFMS is the channel for payment, accounting and reporting under Direct Benefit Transfer.
- Every Ministry/Department/Agency of Centre and States, transfers funds electronically to beneficiary through PFMS.

- PFMS प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत भुगतान, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए चैनल है।
- केंद्र और राज्यों का प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/एजेंसी, PFMS के माध्यम से लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित करता है।

Public Financial Management System PFMS

- It comes under Controller General of Accounts (not CAG)
- It is integrated with core banking system of banks
- It does efficient cash management for govt by:
  - Direct Benefit Transfer
  - Just-in-time release of funds
  - and much more…

Treasury Single Account

- It consolidates multiple accounts into a single account
- It is operationalized through PFMS
- Many autonomous bodies of govt are using it

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS

- यह कंट्रोलर जनरल ऑफ़ एकाउंट्स (CAG नहीं) में आता है
- यह बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत है
- यह सरकार के लिए कुशल नकदी प्रबंधन करता है:
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
  - धन की समय-समय पर रिहाई
  - और भी बहुत कुछ...

ट्रेज़री सिंगल अकाउंट

- यह कई खातों को एक ही खाते में समेकित करता है
- इसका संचालन PFMS के माध्यम से किया जाता है
- सरकार के कई स्वायत्त निकाय इसका उपयोग कर रहे हैं

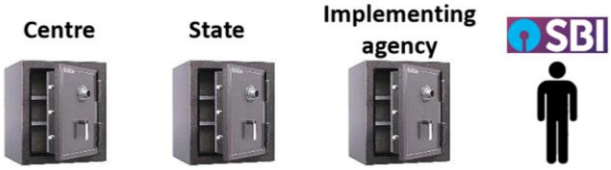

Self Help Group

Informal group of 10-20 individuals, of similar socio-economic status, coming together to save small sum of money and for mutual help.

समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले 10-20 व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह, जो छोटी राशि बचाने और आपसी मदद के लिए साथ आता है।

Functions

- ✓ Build capacity in income generating activity
- ✓ Solve problems by mutual discussions
- ✓ Develop savings habit in members
- ✓ Give collateral free loan to members

- ✓ आय सृजन गतिविधि में क्षमता निर्माण
- ✓ आपसी विचार-विमर्श से समस्याओं का समाधान
- ✓ बचत की आदत विकसित करना
- ✓ कोलैटरल फ्री लोन देना

https://www.thehindu.com/business/Economy/self-help-groups-can-help-in-widening-womens-labour-force-participation-economic-survey/article66454927.ece

- India has around 1.2 crore SHGs, 88% of them all-women.
- SHG success stories include Kudumbashree in Kerala, Jeevika in Bihar, Mahila Arthik Vikas Mahamandal in Maharashtra and recently, Looms of Ladakh.
- SHG Bank Linkage Project (SHG-BLP), launched in 1992, is world's largest microfinance project.

- भारत में 1.2 करोड़ SHG हैं, जिनमें से 88% में केवल महिलाएं हैं
- SHG की सफलता की कहानियों में केरल में कुदुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल और हाल ही में, लद्दाख के लूमस शामिल हैं।
- 1992 में शुरू किया गया SHG-BLP, दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना है।

Some govt initiatives:

- 1992: SHG Bank Linkage Project (SHG-BLP) by NABARD. Banks were allowed to open savings account for SHG and give loans without collateral. Loan amount can be several times the deposit of the SHG.
- 1993: Rashtriya Mahila Kosh (Ministry of Women & Child Development). It gives loans to NGOs-MFI who then lend to women SHGs.
- 1999: Swarn Jayanti Gram Swarojgaar Yojana to promote formation and skilling of SHGs.
- 2011: National Rural Livelihoods Mission

- 1992: नाबार्ड द्वारा SHG बैंक लिंकेज परियोजना (SHG-BLP)। बैंकों को SHG के लिए बचत खाता खोलने और बिना संपार्श्विक के ऋण देने की अनुमति दी गई थी । ऋण राशि SHG की जमा राशि से कई गुना अधिक हो सकती है।
- 1993: राष्ट्रीय महिला कोष (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) यह NGO-MFI को ऋण देता है जो फिर महिला SHG को ऋण देते हैं
- 1999: SHG के गठन और कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- 2011: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

Prelims 2023 Consider the following statements:

1. The Self-Help Group (SHG) programme was originally initiated by the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived. NO
2. In an SHG, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. YES
3. The Regional Rural Banks and Scheduled Commercial Banks support SHGs. YES

How many of the above statements are correct?
(a) Only one (b) Only two (c) All three (d) None

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. स्वयं सहायता समूह (SHG) कार्यक्रम मूलत: भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था।
2. किसी SHG में, एक समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं, जो ऋण एक अकेला सदस्य लेता है।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन देते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Microfinance

Microfinance:
Term first used in 1970s during development of Grameen Bank of Bangladesh (1976), founded by Muhammad Yunus. They got 2006 Nobel Peace prize.

माइक्रोफाइनेंस / सूक्ष्म वित्त
इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1970 के दशक में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश (1976) के विकास के दौरान किया गया था, जिसकी स्थापना मुहम्मद यूनुस ने की थी। उन दोनों को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।

Malegam Committee 2011 is related to?
➢ Microfinance sector; by RBI

मालेगाम समिति 2011 किससे संबंधित है?
➢ माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र; RBI द्वारा

https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12256&Mode=0

- ✓ All collateral-free loans given to a household with annual income up to ₹ 3,00,000
- ✓ Interest rates should not be usurious (RBI has not fixed the rates or put any upper limit)
- ✓ EMI should not exceed 50% of monthly income
- ✓ Can't use harsh recovery practice (e.g. abusive language, publishing names, harassing relatives)
- ✓ No penalty for pre-payment
- ✓ Same regulations for all banks and NBFCs

Loans up to ₹ 3 lakh are micro loans? No

- ✓ ₹ 3,00,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिए गए सभी संपार्श्विक-मुक्त ऋण
- ✓ ब्याज दरें सूदखोरी नहीं होनी चाहिए (RBI ने दरें तय नहीं की हैं, न ही कोई ऊपरी सीमा लगाई है)
- ✓ EMI मासिक आय के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ✓ कठोर पुनर्प्राप्ति अभ्यास का उपयोग नहीं कर सकते (जैसे अपमानजनक भाषा, नाम प्रकाशित करना, रिश्तेदारों को परेशान करना)
- ✓ प्री-पेमेंट के लिए कोई जुर्माना नहीं
- ✓ सभी बैंकों और NBFC के लिए समान नियम

₹ 3 लाख तक के ऋण सूक्ष्म ऋण हैं? नहीं

Prelims 2011
Microfinance is the provision of financial services to people of low-income groups. This includes both the consumers and the self-employed. The services rendered under microfinance are:
1. Credit facilities 2. Savings facilities
3. Insurance facilities 4. Fund Transfer facilities
Select the correct answer
(a) 1 only (b) 1 and 4 only
(c) 2 and 3 only (d) 1, 2, 3 and 4

माइक्रोफाइनेंस कम आय वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान है। इसमें उपभोक्ता और स्वरोजगार दोनों शामिल हैं।
माइक्रोफाइनेंस के तहत प्रदान की जाने वाली सेवा/सेवाएं हैं:
1. ऋण सुविधाएं 2. बचत सुविधाएं
3. बीमा सुविधाएं 4. फंड ट्रांसफर सुविधाएं
सही उत्तर का चयन कीजिए
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4